लगाए जाने वाले उपयुक्त मूल्य के दियासलाई-उत्पादन-शुल्क फीतों द्वारा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क वसूल करने की प्रणाली बन्द कर दी गई है, क्योंकि फीतों को छपवाने और वितरित करने में राजकोष का काफी व्यय होता था। साथ ही, उद्योग को भी फीते लगाने की मजदूरी के रूप में काफी व्यय करना पड़ता था। इसके अलावा, स्वनिर्धारण पर निकासी की कार्यविधि में भी यह प्रणाली ठीक नहीं बैठती है जिसको केन्द्रीय उत्पादन शुल्क लगने योग्य विभिन्न वस्तुओं के संबंध में चालू किया गया है। इन वस्तुओं में दियासलाई भी शामिल है। रोकथाम संबंधी बहुत-सी जांचों के अतिरिक्त, कच्चे माल और तैयार माल का पारस्परिक मिलान किया जाता है जिससे यह इतमीनान हो जाय कि सारे उत्पादन को हिसाब में ले लिया गया है और शुल्क का कोई अपवंचन नहीं हुआ है।

(ग) और (घ). दियासलाइयों पर फीता लपेटने की प्रणाली 1 अक्टूबर, 1968 से बन्द की गई थी। उक्त तारीख से एक वर्ष पहले और एक वर्ष बाद की अवधियों के दौरान तथा उक्त तारीख से तीन महीने पहले और तीन महीने बाद की अवधियों के दौरान दियासलाइयों के उत्पादन, निकासी और वसूल किए गए केन्द्रीय उत्पादन शुल्क का विवरण-पत्र सभा की मेज पर रख दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या** LT–3015/70]

(ङ) हालांकि यह कहा जा सकता है कि फीते लगाने की प्रणाली बंद करने के तुरंत बाद कुछ समय के लिए शुल्क की उगाही थोड़ी सी कम हुई है, फिर भी पुरानी परिपाटी को पुनः अपनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Houses to Displaced People on No-profit and No-Loss Basis

***685. SHRI BAL RAJ MADHOK: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:**

(a) whether it is a fact that Government stands committed to give houses to the displaced people in its colonies on no-profit and noloss basis;

(b) whether it is also a fact that Government are demanding prices for the land in such colonies much above the cost of land nd its development as itself admitted by Government in some of its notes and communications;

(c) whether it is also a fact that Government are contemplating a steep increase in base money for such lands after the completion of twenty years;

(d) if so, whether it will not amount to a breach of faith and injustice to the displaced persons; and

(e) whether Government will discuss the whole matter with the representatives of the colonies and their elected representatives in Parliament before proceeding further in this matter?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI K. K. SHAH): (a) to (e). The information required is being collected and will be laid on the Table of the House.

Establishment of Coordination between Research and Industry

***686. SHRI G. Y. KRISHNAN: Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS AND MINES AND METALS be pleased to state:**

(a) whether Government have taken any specific steps to establish co-ordination between research and industry particularly in the field of Steel, Chemicals and Instrumentation industries;

(b) what measures have been taken to reorganise and improve science administration structure; and

(c) whether a high level working group of Young Indian Scientists working abroad is proposed to be set up to improve the situation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS, AND MINES AND METALS (SHRI D. R. CHAVAN): (a) Yes, Sir. An Expert Committee has been constituted by the Council of Scientific and Industrial Research consisting of representatives of the Steel, Chemical, Instruments and Engineering industry, Directorate General of Technical Development, Planning Commission and Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry with the following terms of reference:

(i) to provide guidelines to the National Laboratories/Institutes in planning their programmes;

(ii) to identify major areas of importance; and

(iii) to coordinate activities of the National Laboratories/Institutes with the public and private sector industries.

(b) Reorganisation and improvement of Science Administration Structure is a continuing effort and the policies regarding the organisation structure cannot be visualised as a permanent frame-work. A committee on Organisation of Scientific Research has been constituted to look into the isolated departments of Government to give them a viable and flexible character so as to enable them to discharge their functions more effectively.

(c) No, Sir.

जीवन बीमा निगम की किसानों के लिए फसल बीमा योजनायें

*687. **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री रा० बरुआ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसानों के लाभ के लिए जीवन बीमा निगम ने फसल बीमा योजना आरम्भ करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का विचार कब तक इस योजना को क्रियान्वित करने का है ?

वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) जी, नहीं। मामले का अध्ययन किया जा रहा है।

(ख) और (ग). ये सवाल नहीं उठते।

प्रस्तावित तीसरे वेतन आयोग का अध्यक्ष बनने से कुछ व्यक्तियों द्वारा इंकार

*689. **श्री श्रीगोपाल साबू :**
श्री राम गोपाल शालवाले :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री टी० पी० शाह :
श्री भारत सिंह चौहान :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित तीसरे वेतन आयोग की नियुक्ति इस कारण स्थगित की गई है क्योंकि प्रस्तावित आयोग का अध्यक्ष बनने से कुछ व्यक्तियों ने इन्कार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त आयोग का अध्यक्ष बनने से उनका इन्कार करने का कारण यह है कि सरकार वेतन आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं करती;

(घ) क्या सरकार का विचार लोक सभा के चालू सत्र के मध्य तक तीसरा वेतन आयोग नियुक्त करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए तीसरे वेतन आयोग की अध्यक्षता करने के लिए सरकार द्वारा आमंत्रित किए गए व्यक्तियों के नाम क्या हैं ?